वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० च द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न देशों/संस्थाओं से सरकारी और गैर-सरकारी खाते के संबंध मे प्राप्त विदेशी सहायता क्रमश. 11022 करोड़ रुपये, 11781 करोड़ रुपय और 10476 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी ।

(ग) और (घ) मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज के भुगतान की राशि वर्ष 1992-93 में क्रमश: 4788 करोड़ रुपये और 3961 करोड़ रुपये, वर्ष 1993-94 में क्रमश: 5353 करोड़ रुपये और 4199 करोड़ रुपये और वर्ष 1994-95 के दौरान क्रमश: 5841 करोड रुपये (अनन्तिम) और 4386 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी ।

(ङ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1995-96 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी खाते के संबंध में विदेशी ऋण की बकाया राशि क्रमश: 127376 करोड़ रूपये, 135501 करोड़ रूपये और 150798 करोड़ रूपये (अनन्तिम) थी ।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता की राशि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, आधार-भूत संरचना सामाजिक और शहरी विकास आदि में निवेश की गई है । इन क्षेत्रों में निवेश की गई राशि विदेशी सहायता पुस्तिका में प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी हुई हैं ।

Total tax collections

6035. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

SHRI G. G. SWELL:

SHRI P. UPENDRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the last seven years the total tax collection of Central Government has almost doubled;

(b) whether it is a fact that during the period the GDP has more than doubled;

(c) whether it is a fact that during last two years the average tax rate has gone down and yet the tax revenue has gone up; and

(d) whether it is because of better compliance due to lower taxation; and

(e) whether it is a fact that one of the most important reason for growth in industrial production is reduction in the rate of taxation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The increase in tax collection is due to better compliance among other reasons;

(e) Several factors, including reduction in rates of taxation and rationalisation of tax laws, have facilitated growth in industrial production.